(b) whether they have failed to fulfil the export obligation stipulated in their licences;

(c) whether the Champagne India Ltd. is one of these units; and

(d) what action Government have taken against these units for non-fulfilment of export obligation?

THE MINISTER OF COMMERCE AND FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) A list of six Units approved under 100 per cent Export Oriented Unit Scheme for manufacture of various types of alcoholic beverages is appended in the annexed statement (*see below*).

(b) Out of these six Units the letter of intent in respect of M/s. Transparent Distilleries & Bottlers, New Delhi, M/s. Champagne India Ltd., Bombay and M/s. Breweries India Private Ltd., Trivandrum has been converted into Industrial Licence on 19-1-1984, 29-7-1985 and 14-11-1985 respectively. As per the conditions of the Industrial Licence, none of these firms have failed to fulfil the export obligation.

(c) Yes, Sir. M/s. Champagne India Ltd., Bombay has already started production and export.

(d) Question does not arise.

Statement

Sl. No.	Name of the Unit
1	Gowthani Agro Industries Private Ltd., Eluru.
2	Breweries India Private Ltd., Trivandrum.
3	M/s. Nag Agro, Gandhi Bagh, Nagpur.
4	Skol Breweries Ltd., Bombay.
5	Champagne India Ltd., Bombay.
6	Transparent Distilleries & Bottlers, New Delhi.

Misuse of advance import licence facilities

898. SHRI SURESH PACHOURI:
SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:
SHRI GULAM MOHI-UD-DIN SHAWL:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Enforcement Wing of the Chief Controller of Exports and Imports has detected large scale misuse of advance import licence facilities;

(b) if so, whether the misuse of import licence by the two Gujarat based companies were detected in the month of January, 1986;

(c) if so, what action has been taken against the companies; and

(d) what steps are being taken to check the misuse of import licences on a large scale?

THE MINISTER OF COMMERCE AND FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The applications for import licence and allotment of canalised items have been placed under abeyance in respect of M/s. L. D. Textiles Industries, Ankleshwar. The operation of import licences already issued has been suspended and a show cause notice for cancellation of the same has been issued. The licensing authority has been advised to recover Customs duty and enforce bank guarantee conditions. A combined show cause notice for debarment and fiscal penalty is also being issued besides referring the matter to C.B.I. for investigation.

In case of M/s. Universal Dyestuffs Industries Ltd., Baroda, a show cause notice under the Act is being issued and the matter referred to C.B.I. for

detailed investigation. The genuineness of entries made in the DEEC Book is also being verified.

(d) Under advance licence scheme, import of raw materials etc. is allowed for export production. Imported material not used in export product cannot be disposed of otherwise except with the permission of the licensing authority concerned. In case of misuse of imported material action will lie under the Imports and Exports (Control) Act and the Order issued thereunder, in addition to the forfeiture of bank guarantee.

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

899. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों के पुनः वर्गीकरण के बाद से संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पर्यटन विभाग हेतु प्रथक हिंदी सलाहकार समिति गठित करने का भी विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) तत्कालीन पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय से पर्यटन विभाग के प्रथक हो जाने के बाद, अब यह निर्णय लिया गया है कि पर्यटन विभाग के लिए अलग से एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर लिया जाए । समिति के गठन को संसदीय कार्य विभाग, राजभाषा से विभाग आदि से परामर्श करते हुए अंतिम रूप दिया रहा है ।

सितम्बर, 1985 से संसदीय कार्य विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है । इस समिति की अब तक दो बैठकें हुई हैं ।

बंधुआ श्रम

900. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्धुआ मजदूर की क्या परिभाषा है और क्या सरकारी विभागों/उपक्रमों में इन्हीं परिस्थितियों में कार्य करने वाले व्यक्ति इस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते, और यदि हां, तो इस प्रकार के कानून की उपयोगिता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय बन्धुआ मजदूर अर्थात डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारियों को कर्मचारी नहीं मानता, हालांकि उन्हें सभी प्रकार के दायित्व सौंपे जाते हैं तथा जिन विभागेतर डाकपालों के घरों में ये डाक घर चलाते हैं, उन्हें किराये या मरम्मत प्रभारों की बात तो अलग, सफाई प्रभार भी अदा नहीं किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या विभाग इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने का विचार रखता है, और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) "बंधित श्रमिक" और "बंधित श्रम पद्धति" की परिभाषा जैसे बंधित श्रम पद्धति (उत्पसादन) अधिनियम 1976 में दी गई है, उसे संलग्न विवरण में उद्धृत किया गया है (नीचे) देखिये । चूंकि डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारी इन शर्तों को पूरा नहीं करते, इसलिए उन्हे बंधुआ श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।